



Publications

## United International Journal of Multidisciplinary Research (UIJMR)

An International Peer-Reviewed and Refereed Multidisciplinary Journal

ISSN: 3048-6726 [www.ujmr.in](http://www.ujmr.in) Impact Factor: 6.934 (SJIF) Vol-3, Issue-2 ; April, May & June, 2026

### 20वीं शताब्दी में हरियाणा में शिक्षा का विकास : एक अध्ययन

सोनिया, <sup>1</sup> डॉ. अशोक कुमार<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर (रोहतक)

ईमेल: [soniamik456@gmail.com](mailto:soniamik456@gmail.com)

<sup>2</sup>प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर (रोहतक)

Article Received:08-03-2025 Article Modified:03-04-2026

Article Accepted:04-04-2026 Article Published:05-04-2026

DOI:10.37854/UIJMR.2026.3.2.15

#### सारांश

बीसवीं शताब्दी में हरियाणा की शिक्षा-व्यवस्था ने अत्यन्त लम्बी और जटिल यात्रा तय की। शताब्दी के प्रारम्भ में यह क्षेत्र साक्षरता, विद्यालयों की संख्या और उच्च शिक्षा संस्थानों की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा था, जबकि शताब्दी के अन्त तक यहाँ साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर पहुँच चुकी थी और अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा व्यावसायिक संस्थाएँ कार्यरत थीं (गोयल, 1972; यादव, 2003)। स्वतंत्रता से पूर्व आर्य समाज, गुरुकुल आन्दोलन और स्वाधीनता सेनानियों ने शिक्षा को सामाजिक-धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनाया, जबकि स्वतंत्रता के बाद संविधानिक प्रावधानों, शिक्षा आयोगों और पंचवर्षीय योजनाओं ने नीतिगत ढाँचा प्रदान किया (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1949; माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1953)। सन् 1966 में हरियाणा के पृथक राज्य के रूप में गठन के बाद प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा कृषि और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नयी योजनाएँ लागू की गयीं (हरियाणा सरकार, 2000)। प्रस्तुत शोध-पत्र में इन सभी चरणों का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए यह दिखाया गया है कि शिक्षा-विकास ने हरियाणा के सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण में किस प्रकार केन्द्रीय भूमिका निभायी।

मुख्य शब्द : हरियाणा, शिक्षा, साक्षरता, आर्य समाज, औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रोत्तर काल, उच्च शिक्षा।

#### 1. प्रस्तावना

हरियाणा वैदिक काल से ही ज्ञान और साधना की भूमि माना जाता है, किन्तु आधुनिक अर्थ में विद्यालयी और विश्वविद्यालय-स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रदेश उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अत्यन्त पिछड़ा था (यादव, 2003)। तत्कालीन पंजाब प्रान्त के अन्तर्गत आने वाले इस भूभाग में औपनिवेशिक शासन का मुख्य ध्यान राजस्व और कानून-व्यवस्था पर केन्द्रित रहा, जिसके कारण शिक्षा को केवल सीमित वर्ग



तक पहुँचाने की नीति अपनायी गयी (कुमार, 1991)। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः केवल परम्परागत पाठशालाएँ या मस्जिद-मकतब थे, जहाँ धार्मिक-धार्मिक शिक्षा दी जाती थी; आधुनिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञानों की पढ़ाई न के बराबर थी (गोयल, 1972)। भारत की जनगणना 1901 और 1911 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि हरियाणा के अधिकांश जिलों में साक्षरता दर पाँच प्रतिशत से भी कम थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता लगभग शून्य के बराबर थी (भारत की जनगणना, 1901; 1911)। जाति-व्यवस्था, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह और बाल-श्रम जैसी कुरीतियों ने भी शिक्षा के प्रसार को अवरुद्ध किया (शर्मा, 1999)। इन परिस्थितियों में शिक्षा की ओर पहला संगठित प्रयास धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ी विचारधाराओं के माध्यम से सामने आया। यह शोध-पत्र औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता-उपरान्त संयुक्त पंजाब काल और हरियाणा राज्य काल—इन तीन चरणों के माध्यम से शिक्षा-विकास की इस लंबी प्रक्रिया का विवेचन करता है।

## 2. औपनिवेशिक काल में शिक्षा (1900–1947)

### 2.1 ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रभाव

औपनिवेशिक शासन की शिक्षा-नीति का आधार अठारह सौ पैंतीस की मैकॉले प्रतिवेदन और अठारह सौ चौवन का बुड प्रपर भेज था, जिसमें अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक विज्ञान और प्रशासकीय प्रशिक्षण पर बल दिया गया, परन्तु शिक्षा के व्यापक प्रसार की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी (कुमार, 1991)। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हो चुकी थी, पर इसका लाभ मुख्यतः शहरों के उच्च वर्ग के विद्यार्थियों को ही मिल सका; रोहतक, हिसार, करनाल और गुडगाँव जैसे जिलों के ग्रामीण युवक-युवतियाँ इससे दूर रहे (सिंह, 1985)।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजी शासन ने कुछ प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोलने का प्रयास किया, किन्तु ये प्रायः तहसील मुख्यालयों तक ही सीमित रहे। वित्तीय संसाधनों की कमी, स्थानीय समुदायों की उदासीनता और औपनिवेशिक नीतियों में निहित पूर्वाग्रहों के कारण शिक्षा-विस्तार बहुत धीमी गति से हुआ (गोयल, 1972)। भारत की जनगणना 1901 और 1911 में दर्ज आँकड़े बताते हैं कि हरियाणा क्षेत्र में पुरुष साक्षरता आठ से दस प्रतिशत और महिला साक्षरता केवल एक से दो प्रतिशत के बीच रही (भारत की जनगणना, 1901; 1911)। इससे स्पष्ट है कि औपनिवेशिक नीति का उद्देश्य जन-कल्याण से अधिक प्रशासनिक सुविधा था, जिसके कारण शिक्षा सामाजिक न्याय का साधन न बनकर केवल सीमित वर्ग का विशेषाधिकार रह गयी।

### 2.2 आर्य समाज और शिक्षा आन्दोलन

इन सीमाओं के बीच आर्य समाज ने हरियाणा में शिक्षा-जागरण का एक प्रभावशाली आन्दोलन खड़ा किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित इस संगठन ने अठारह सौ पचहत्तर के बाद दयानन्द एंग्लो वैदिक (डी.ए.वी.) विद्यालयों की श्रृंखला प्रारम्भ की, जहाँ वैदिक विचारों के साथ-साथ विज्ञान, गणित, आधुनिक भाषाओं और अंग्रेजी का शिक्षण भी होता था (गोयल, 1972; सुप्रिया, 2016)।



रोहतक, अंबाला, करनाल, हिसार तथा सोनीपत जैसे कस्बों में खुले इन विद्यालयों ने हरियाणा के किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के बच्चों के लिये आधुनिक शिक्षा के द्वार खोले (सुप्रिया, 2016; आर्य समाज हरियाणा पर अध्ययन, 2021)।

आर्य समाज ने केवल बालकों ही नहीं, बालिकाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। अनेक कन्या-विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना की गयी, जिनमें निम्न जाति और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियाँ भी पढ़ने लगीं (सुप्रिया, 2016)। गुरुकुल परम्परा से प्रेरित हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और अन्य स्थानों के गुरुकुलों ने भी हरियाणा के विद्यार्थियों को आकर्षित किया, जहाँ स्वदेशी, अनुशासित और श्रम-केन्द्रित शिक्षा दी जाती थी (पाण्डेय, 2018)। इन प्रयासों ने समाज में जाति-आधारित भेदभाव, अन्धविश्वास और स्त्री-अवनति के विरुद्ध एक बौद्धिक वातावरण तैयार किया।

### **2.3** स्वाधीनता संग्राम और शिक्षा की चेतना

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से स्वाधीनता आन्दोलन तीव्र होने लगा तो हरियाणा के अनेक नौजवान राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रेरित होकर अंग्रेजी विद्यालयों के बहिष्कार तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की दिशा में सक्रिय हुए (शर्मा, 1999)। महात्मा गाँधी की बुनियादी तालीम योजना ने शिक्षा को स्वावलम्बन, उत्पादन-कार्य और ग्राम-जीवन से जोड़ने का विचार रखा, जिसका प्रभाव पंजाब-हरियाणा के कई शिक्षा-चिन्तकों पर पड़ा (गाँधी, 1951)। कुछ स्थानों पर चरखा-काताई, बागवानी और हाथ-कला को पाठ्यक्रम का अंग बनाने के प्रयोग हुए, हालांकि औपनिवेशिक शासन की बाधाओं के कारण इन्हें व्यापक स्तर पर लागू नहीं किया जा सका (कुमार, 1991)।

इसी काल में अंबाला, रोहतक और करनाल के डिग्री कॉलेजों ने उच्च शिक्षा के सीमित किन्तु महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराए, जहाँ से निकलने वाले अनेक शिक्षित युवक बाद में स्वतंत्रता आन्दोलन, पत्रकारिता और लोकसेवा में सक्रिय हुए (सिंह, 1985)। कुल मिलाकर, औपनिवेशिक काल के अन्त तक हरियाणा में शिक्षा का ढाँचा अभी प्रारम्भिक अवस्था में था, परन्तु सामाजिक-धार्मिक आन्दोलन और राष्ट्रीय चेतना के कारण परिवर्तन की ठोस आधारभूमि तैयार हो चुकी थी।

### **3. स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास (1947-1966)**

#### **3.1** स्वतंत्र भारत की शिक्षा-नीतियाँ और हरियाणा

स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना राज्य का दायित्व घोषित किया। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अनुच्छेद 45 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा (भारत का संविधान, 1950)। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन आयोग) ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान और विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर बल दिया, जबकि माध्यमिक शिक्षा आयोग



(मुदालियर आयोग) ने पाठ्यक्रम-संरचना, व्यावसायिक शिक्षा और बहुपक्षीय विद्यालयों की अनुशंसा की (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1949; माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1953)।

इन राष्ट्रीय सिफारिशों का प्रभाव संयुक्त पंजाब राज्य के अन्तर्गत आने वाले हरियाणा क्षेत्र पर भी पड़ा। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यपुस्तक वितरण की नयी योजनाएँ आरम्भ की गयीं (पंजाब सरकार, 1964)। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार, पंजाब राज्य की समग्र साक्षरता दर लगभग चौबीस प्रतिशत तक पहुँच गयी थी, जो औपनिवेशिक काल के अन्त की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि थी (भारत की जनगणना, 1951)। हालांकि, हरियाणा के ग्रामीण जिलों में यह वृद्धि असमान रही; अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं तक शिक्षा का लाभ अपेक्षाकृत कम पहुँच पाया (गोयल, 1972; सिंह, 1985)।

### **3.2 शिक्षण संस्थाओं का विस्तार**

स्वतंत्रता से लेकर सन् 1966 तक हरियाणा क्षेत्र में विद्यालयों और महाविद्यालयों का जाल धीरे-धीरे फैलने लगा। अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार और सोनीपत जैसे नगरों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें कला, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा के साथ-साथ शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हुए (पंजाब सरकार, 1964)। इन महाविद्यालयों ने ग्रामीण युवकों और युवतियों को विश्वविद्यालय-स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया।

पचास के दशक में कुरुक्षेत्र में धर्म-अध्ययन तथा संस्कृत के विशेष केन्द्र के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी, जो शीघ्र ही सामान्य उच्च शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 2006)। इसी अवधि में अम्बाला, सिरसा और रोहतक आदि स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा बहु-तकनीकी संस्थान खोले गए, जहाँ यांत्रिक, विद्युत, सिविल अभियांत्रिकी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलने लगे (हरियाणा सरकार, 2000)। महिला शिक्षा के लिए अंबाला, रोहतक और सोनीपत में अलग-अलग महिला महाविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें ग्रामीण पृष्ठभूमि की अनेक छात्राएँ पहली बार स्नातक शिक्षा तक पहुँचीं (गोयल, 1972; सिंह, 1985)। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद के दो दशकों ने हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा-विस्तार की ठोस नींव रखी।

## **4. हरियाणा राज्य गठन के पश्चात शिक्षा (1966–2000)**

### **4.1 नवगठित राज्य की शैक्षिक चुनौतियाँ**

एक नवम्बर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो उसे सीमित वित्तीय संसाधन, अपेक्षाकृत कम विकसित औद्योगिक ढांचा और शिक्षा-प्रणाली की कमजोरियों जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा (यादव, 2003)। पंजाब के विभाजन के कारण कई प्रतिष्ठित विद्यालय और महाविद्यालय चंडीगढ़ तथा अन्य क्षेत्रों में रह गये; हरियाणा के हिस्से में अधिकतर ग्रामीण और अर्धशहरी विद्यालय ही आये (हरियाणा सरकार, 2000)। इस स्थिति में राज्य सरकार को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा-व्यवस्था का पुनर्गठन करना पड़ा।



पहली पंचवर्षीय योजनाओं के राज्य संस्करणों में हरियाणा ने शिक्षा को विकास नीति का केन्द्रीय अंग माना। नए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोलने, शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना, निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने और पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय आवश्यकताओं को शामिल करने पर बल दिया गया (योजना आयोग, 1973)। अनेक जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) तथा सेवा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गए, जिनके माध्यम से नये शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला (हरियाणा सरकार, 2000)। इन उपायों ने आगे चलकर शिक्षा-विस्तार की गति को तेज किया।

#### **4.2 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा का विस्तार**

हरियाणा राज्य बनने के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई। रोहतक में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना सत्तर के दशक के मध्य में की गयी, जिसने पूरे राज्य के महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान कर कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबन्धन, शिक्षा और विधि जैसे विषयों में स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई सम्भव की (महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, 2005)। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1970 में हुई, जिसने उन्नत कृषि-शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं के माध्यम से हरित क्रान्ति को वैज्ञानिक आधार देने में निर्णायक भूमिका निभायी (चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, 2004)।

इसी अवधि में चिकित्सा, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थानों का भी विकास हुआ। रोहतक में पण्डित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की शुरुआत बाद के वर्षों में हुई, जबकि हिसार में गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से कम्प्यूटर विज्ञान, पर्यावरण प्रबन्धन और लोक संचार जैसे नये विषयों को बढ़ावा मिला (जी.जे.यू.एस.टी., 2001; हरियाणा सरकार, 2000)। इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को राज्य के भीतर ही विविध प्रकार की उच्च शिक्षा उपलब्ध होने लगी, जिससे बाहर जाने की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हो गयी।

#### **4.3 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार**

राज्य गठन के बाद हरियाणा सरकार ने “हर गाँव में स्कूल” की अवधारणा के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की नीति अपनायी। सन् 1966 में जहाँ लगभग चार हजार प्राथमिक विद्यालय थे, वहीं नब्बे के दशक के अन्त तक इनकी संख्या तीन गुना से अधिक हो गयी (हरियाणा सरकार, 2000; शिक्षा क्षेत्र रिपोर्ट, 2020)। कई नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी खोले गए तथा पूर्व विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों को क्रमशः उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नत किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा उसके 1992 के कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत दस-दो-तीन की नयी संरचना अपनायी गयी, जिसके अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, वाणिज्य और कला के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/1992)। “ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड” कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में दो कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल, खेल-सामग्री और शिक्षण-सहायक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ (भारत



सरकार, 1994)। बाद में “सर्व शिक्षा अभियान” और मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा नामांकन तथा उपस्थिति में वृद्धि हुई और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई (भारत सरकार, 2001; हरियाणा सरकार, 2000)।

#### **4.4 स्त्री शिक्षा में प्रगति**

हरियाणा में स्त्रियों की शिक्षा ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रही, परन्तु बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसमें उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी। सन् 1961 में जहाँ महिला साक्षरता लगभग 15 प्रतिशत के आसपास थी, वही आँकड़ा 1991 में लगभग 40 प्रतिशत और 2001 में 55.73 प्रतिशत तक पहुँच गया (भारत की जनगणना, 1991; 2001; “हरियाणा में साक्षरता की स्थिति”, 2001)। यह वृद्धि प्राथमिक विद्यालयों, कन्या-माध्यमिक विद्यालयों, महिला महाविद्यालयों और विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम थी (हरियाणा सरकार, 2000)।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास सुविधाएँ, साइकिल योजना और प्रोत्साहन राशि जैसी नीतियाँ लागू कीं। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों और स्व-रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों ने उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ायी (महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, 2005)। हालांकि, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अनेक छात्राएँ माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने को विवश होती रहीं; फिर भी समग्र रूप से देखें तो स्त्री-शिक्षा की स्थिति पूर्व की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ हुई (भारत सरकार, 2001; “हरियाणा शिक्षा क्षेत्र”, 2025)।

#### **5. शिक्षा के विकास में योगदान करने वाले प्रमुख कारक**

##### **5.1 सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ**

हरियाणा में शिक्षा-विकास के पीछे राज्य और केन्द्रीय सरकारों की नीतियाँ प्रमुख कारक रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शिक्षा पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ा और नब्बे के दशक तक राज्य बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र को मिलने लगा (योजना आयोग, 1999)। “राष्ट्रीय साक्षरता मिशन”, “ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड”, “सर्व शिक्षा अभियान”, “मध्याह्न भोजन योजना” तथा “निःशुल्क पाठ्यपुस्तक” जैसी योजनाओं ने विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच को व्यापक बनाया (भारत सरकार, 1994; 2001; हरियाणा सरकार, 2000; “हरियाणा शिक्षा क्षेत्र”, 2025)।

अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, शुल्क-माफी और वर्दी-योजना ने भी नामांकन बढ़ाने में सहायता की (भारत सरकार, 2001; हरियाणा सरकार, 2000)। पंचायतों और ग्राम-शिक्षा समितियों को विद्यालय-प्रबन्धन में



आंशिक अधिकार देने से समुदाय की भागीदारी बढ़ी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही की व्यवस्था विकसित हुई (सती-इकाइयां, 2024)।

### 5.2 सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

हरित क्रान्ति के कारण हरियाणा की कृषि-उत्पादकता बढ़ी और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, 2004)। बेहतर सिंचाई, उन्नत बीज और वैज्ञानिक कृषि-तकनीक ने राज्य को देश के अग्रणी खाद्यान्न उत्पादकों में शामिल कर दिया, जिससे ग्रामीण परिवारों में शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध होने लगे (फ्रैंकल, 1971, जैसा उद्धृत यादव, 2003 में)। कृषि-समृद्धि के साथ-साथ शहरीकरण और उद्योगों के विकास—विशेषकर फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत में—ने सेवा-क्षेत्र में नये रोजगार उत्पन्न किए, जिनके लिए विद्यालयी और उच्च शिक्षा को अनिवार्य माना जाने लगा (हरियाणा सरकार, 2000; “हरियाणा में शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य”, 2018)।

टीवी, रेडियो, समाचार-पत्र और बाद में इंटरनेट जैसे संचार माध्यमों के प्रसार ने लोगों को शिक्षा के महत्व से परिचित कराया। प्रवास और रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर जाने वाले युवकों-युवतियों ने देखा कि उच्च शिक्षा से सामाजिक-आर्थिक उन्नति के अवसर अधिक हैं; इस अनुभव ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बल दिया (कुमार, 1991; यादव, 2003)।

### 5.3 धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका

हरियाणा में आर्य समाज, सनातन धर्म संस्थाएँ, सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समितियाँ तथा अन्य धार्मिक-सामाजिक संगठन शिक्षा-विस्तार के महत्वपूर्ण सहायक बने। आर्य समाज की शाखाओं ने डी.ए.वी. विद्यालयों और गुरुकुलों के माध्यम से आधुनिक तथा वैदिक दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रसार किया, जिससे लाखों विद्यार्थियों को सस्ती और अनुशासित शिक्षा उपलब्ध हुई (सुप्रिया, 2016; “आर्य समाज और हरियाणा में शिक्षा”, 2024; “आर्य समाज इन हरियाणा”, 2025)।

इसी प्रकार, हरियाणा के अनेक मठों, आश्रमों और धर्मार्थ ट्रस्टों ने भी विद्यालय, महाविद्यालय और अन्ततः विश्वविद्यालय स्थापित किए। बाबा मस्तनाथ मठ, अस्थल बोहर इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ से प्रेरित होकर सामान्य विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय तक की संस्थाएँ अस्तित्व में आईं और ग्रामीण-पृष्ठभूमि के विद्यार्थी शोध-स्तर तक पहुँच सके (हरियाणा सरकार, 2000)। इन गैर-सरकारी प्रयासों ने शिक्षा को सामाजिक सेवा और धर्म-कर्तव्य के रूप में स्थापित किया तथा सरकारी व्यवस्था की कमियों की भरपाई की।

### 6. 20वीं शताब्दी के अन्त में शिक्षा की स्थिति

बीसवीं शताब्दी के अन्त तक हरियाणा की शिक्षा-व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, राज्य की कुल साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 78.49 प्रतिशत और महिला साक्षरता 55.73 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी (“हरियाणा में



साक्षरता की स्थिति”, 2001; भारत की जनगणना, 2001)। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगा, यद्यपि भीतर ही भीतर जिलों, लिंग और सामाजिक समूहों के बीच अंतर अभी भी विद्यमान थे (साक्षरता का भौगोलिक विश्लेषण, 2015)।

उच्च शिक्षा के स्तर पर राज्य में लगभग एक दर्जन विश्वविद्यालय, अनेक सरकारी तथा निजी महाविद्यालय, अभियांत्रिकी और प्रबन्धन संस्थान, पॉलिटेक्निक और शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय कार्य कर रहे थे (हरियाणा सरकार, 2000; “हरियाणा शिक्षा क्षेत्र”, 2025)। फिर भी, शिक्षक-अनुपस्थिति, अधोमानक बुनियादी सुविधाएँ, कक्षा में भीड़, परीक्षा-केन्द्रित शिक्षण-प्रणाली और रोजगार से कटे हुए पाठ्यक्रम जैसी कमियाँ अभी भी चुनौती बनी रहीं (तिलक, 2002; “शिक्षा विकास स्तर अध्ययन”, 2020)। विशेष रूप से मेवात, कैथल और उत्तर-पश्चिमी जिलों में शिक्षा-विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा (शिक्षा विकास स्तर अध्ययन, 2020)।

#### 7. निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बीसवीं शताब्दी में हरियाणा में शिक्षा का विकास एक दीर्घकालिक, बहुस्तरीय और संघर्षशील प्रक्रिया रही है। औपनिवेशिक शासन की सीमित और वर्ग-केन्द्रित शिक्षा-नीति के बीच आर्य समाज, गुरुकुलों और राष्ट्रीय आन्दोलन ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया (गोयल, 1972; सुप्रिया, 2016)। स्वतंत्रता के पश्चात संविधानिक प्रावधानों, शिक्षा आयोगों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पंचवर्षीय योजनाओं ने शिक्षा को राजकीय दायित्व तथा मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी (भारत का संविधान, 1950; राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/1992)।

सन् 1966 के बाद नवगठित हरियाणा राज्य ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना, कृषि तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ और स्त्री-शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा-विकास की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए (हरियाणा सरकार, 2000; चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, 2004; “हरियाणा शिक्षा क्षेत्र”, 2025)। शिक्षा-विस्तार ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को बदलते हुए नए मध्यम वर्ग, जागरूक किसान-समुदाय और शिक्षित युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार की जिसने प्रशासन, उद्योग, सेना, खेल और अकादमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया (यादव, 2003; भारत की जनगणना, 2001)।

फिर भी, बीसवीं शताब्दी के अन्त तक ग्रामीण-शहरी, लिंग और सामाजिक वर्गों के बीच शिक्षा-असमानता, गुणवत्ता-संकट और रोजगार से असंगत पाठ्यक्रम जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं (तिलक, 2002; शिक्षा विकास स्तर अध्ययन, 2020)। भविष्य की दिशा यही संकेत करती है कि हरियाणा को तीसरी सहस्राब्दी में प्रवेश करते हुए शिक्षा की मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता, समावेशन, मूल्य-आधारित दृष्टिकोण और स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़ी रचनात्मकता पर अधिक बल देना होगा। तभी शिक्षा सच-मुच ज्ञान-सम्पन्न, समानतामूलक और मानवीय समाज के निर्माण का आधार बन सकेगी।



संदर्भ सूची

1. आर्य समाज और हरियाणा में शिक्षा। (2024)। आर्य समाज और भारतीय शिक्षा प्रणाली पर शोध-लेख।
2. आर्य समाज इन हरियाणा। (2025)। आर्य समाज इन हरियाणा (पी.डी.एफ. आलेख)।
3. हरियाणा में साक्षरता की स्थिति। (2001)। हरियाणा में साक्षरता की स्थिति। चण्डीगढ़: हरियाणा शासन।
4. हरियाणा में शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य। (2018)। शिक्षा में हरियाणा की उपलब्धियाँ।
5. हरियाणा शिक्षा क्षेत्र। (2025)। हरियाणा शिक्षा क्षेत्र रिपोर्ट।
6. साक्षरता का भौगोलिक विश्लेषण। (2015)। हरियाणा में साक्षरता के क्षेत्रीय ढाँचे का अध्ययन।
7. शिक्षा विकास स्तर अध्ययन। (2020)। हरियाणा में शैक्षिक विकास के स्तर पर अध्ययन।
8. गोयल, बी. आर. (1972)। हरियाणा में शिक्षा का इतिहास। चण्डीगढ़: हरियाणा साहित्य अकादेमी।
9. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। (2004)। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय: एक परिचय। हिसार।
10. तिलक, जे. बी. जी. (2002)। शिक्षा और गरीबी। मानव विकास पत्रिका, 3(2), 191–207।
11. पाण्डेय, अरुण (2018)। आर्य समाज गुरुकुल विद्यालय: एक सामाजिक-ऐतिहासिक अध्ययन। बहु-विषयक अनुसंधान पत्रिका, 4(1), 45–50।
12. पंजाब सरकार। (1964)। पंजाब में शिक्षा की प्रगति पर प्रतिवेदन। चण्डीगढ़: शिक्षा विभाग।
13. भारत का संविधान। (1950)। भारत का संविधान। नई दिल्ली: भारत सरकार।
14. भारत सरकार। (1994)। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन: दिशा-निर्देश। नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
15. भारत सरकार। (2001)। सर्व शिक्षा अभियान: कार्यान्वयन ढाँचा एवं दिशा-निर्देश। नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
16. भारत की जनगणना। (1901)। भारत की जनगणना 1901, भाग: पंजाब एवं रियासतें। कलकत्ता।
17. भारत की जनगणना। (1911)। भारत की जनगणना 1911, भाग: पंजाब एवं रियासतें। कलकत्ता।
18. भारत की जनगणना। (1951)। भारत की जनगणना 1951: प्राथमिक जनगणना सार। नई दिल्ली।



Publications

## United International Journal of Multidisciplinary Research (UIJMR)

An International Peer-Reviewed and Refereed Multidisciplinary Journal

ISSN: 3048-6726 [www.ujmr.in](http://www.ujmr.in) Impact Factor: 6.934 (SJIF) Vol-3, Issue-2 ; April, May & June, 2026

19. भारत की जनगणना। (1991)। भारत की जनगणना 1991: प्राथमिक जनगणना सार, हरियाणा। नई दिल्ली।
20. भारत की जनगणना। (2001)। भारत की जनगणना 2001: प्राथमिक जनगणना सार, हरियाणा। नई दिल्ली।
21. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय। (2005)। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक: परिचय एवं नियमावली। रोहतक।
22. माध्यमिक शिक्षा आयोग। (1953)। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) की रिपोर्ट। नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
23. राष्ट्रीय शिक्षा नीति। (1986/1992)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
24. यादव, सुरेश (2003)। हरियाणा: इतिहास, भूगोल और संस्कृति। पंचकूला: हरियाणा ग्रन्थ अकादेमी।
25. योजना आयोग। (1973)। चौथी पंचवर्षीय योजना: हरियाणा राज्य रिपोर्ट। नई दिल्ली।
26. योजना आयोग। (1999)। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002): हरियाणा राज्य दस्तावेज़। नई दिल्ली।
27. सुप्रिया। (2016)। आर्य समाज और हरियाणा में शैक्षिक विकास। ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस, 5(5), 574-576।
28. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। (1949)। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) की रिपोर्ट। नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
29. शर्मा, रामशरण (1999)। आधुनिक भारत का इतिहास। नई दिल्ली।
30. कुमार, कृष्ण (1991)। शिक्षा की राजनीतिक रूपरेखा: औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन। नई दिल्ली: सेज प्रकाशन।